कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here



सविनय अवज्ञा की ओर

- असहयोग आंदोलन पूरे देश में व्यापक जनाधार वाला आंदोलन बन गया था। शहरों एवं देहात सभी जगह फैले इस आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया था।
- असहयोग आंदोलन ने जब हिंसक रूप धारण कर लिया तो फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया।
- उनको लगता था सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है।
- कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे।
- जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र–जनांदोलन के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे।
- इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 1920–30 के दशक के आखिरी वर्षों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदल दी।

(i) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर तथा (ii) साइमन कमीशन का गठन

(i) विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर :–

- 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थीं और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गईं।
- कृषि उत्पादों की माँग गिरने से तथा निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा।
- 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल–पुथल से गुजरने लगे थे।

(ii) साइमन कमीशन का गठन :–

- ब्रिटेन की नयी टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया।
- राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन कर उसके बारे में सुझाव देने थे।
- इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था सारे अंग्रेज थे।

साइमन कमीशन का विरोध :–

LET'S LEARN TOGETHER
Download Mission Gyan App

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

- 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुँचा तो उसका स्वागत 'साइमन कमीशन वापस जाओ' (साइमन कमीशन गो बैक) के नारों से किया गया।
- कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।
- साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक आंदोलन का नेतृत्व किया। जिससे अंग्रेज सरकार हिल गयी। अंग्रेजों ने विरोध करने वालों पर लाठियाँ बरसाईं जिसमें 17 नवम्बर 1928 को लाला लाजपत राय शहीद हो गये।
- इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्तूबर 1929 में भारत के लिए 'डोमीनियन स्टेटस' का गोलमोल सा ऐलान कर दिया।
- यद्यपि उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। बस इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज़ सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
- इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे।
- जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस के तेज़-तर्रार खेमे के नेता आक्रामक तेवर अपनाने लगे थे।
- मध्यमार्गी नेता तथा उदारवादी नेता ब्रिटिश डोमीनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था।

पूर्ण स्वराज :-

- दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज' की माँग को औपचारिक रूप से मान लिया गया।
- तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे।
- यद्यपि इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया।

स्वतंत्रता दिवस की शपथ, 26 जनवरी 1930

- 'हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी यह एक अहरणीय अधिकार है कि उन्हें आज़ादी मिले।
- अपनी मेहनत का फल मिले, और जीवन की सभी आवश्यकताएँ पूरी हों जिससे उन्हें आगे बढ़ने के परिपूर्ण अवसर मिलें।
- हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है।
- भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है बल्कि उसने जनता का शोषण किया है।
- उसने देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है।
- इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए।'
- इस प्रकार से हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू तथा कांग्रेसियों का यह पूर्ण स्वराज का सपना था

भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here

कक्षा 6 से 12 तक के सभी विडियोज देखने के लिए Click करें। Click Here

जिसके लिए अभी कुछ वर्षों तक और इंतजार करना था।



Download Mission Gyan App

भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति

PDF का विडियो देखने के लिए Click करें – Click Here